

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:—श्री बी०एल०मेहरड़ा, आर०ए०एस०)

अपील संख्या:—365/2016/225 (2016/00365)

1. सरदार खां पुत्र स्व० फकीर खां,
2. समीर खां पुत्र स्व० फकीर खां,
3. सत्तार खां पुत्र स्व० फकीर खां,
4. पीर खां पुत्र स्व० बोदू खां,
5. उस्मान अहमद पुत्र बोदू खां,
समस्त जाति मुसलमान, नि० मौजमाबाद, तह० मौजमाबाद जिला जयपुर।

अपीलांटस

बनाम

1. नाथू तथाकथित दत्क पुत्र महोदव, जाति रेगर, निवासी मौजमाबाद, तह० मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
3. उप पंजीयक, मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

रेस्पोंडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध विरुद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू दिनांक 23.8.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 138/2013 पुनः दर्ज 411/2013.

उपस्थित:—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री हरिसिंह एवं श्री शोकिन्दलाल गुर्जर, वकील रेस्पोंडेंट संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पोंडेंट संख्या 2.

निर्णय

दिनांक:— 30.9.2019

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के आदेश दिनांक 23.8.2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/अपीलांटस ने अधी०न्याया० में एक वाद विरुद्ध रेस्पोंडेंट संख्या 1 बाबत घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जिसके साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज०काश्त०अधि०के तहत पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम मौजमाबाद में अवस्थित आराजी खसरा नंबर 5075 रकबा 0.66 है०, खसरा नंबर 5076 रकबा 0.86 है०, खसरा नंबर 5077 रकबा 0.63 है० कुल किता 3 कुल रकबा 2.15 है० राजस्व रिकार्ड में महादेव पुत्र रूघा के नाम दर्ज है । आराजियात के पुराने साबिक खसरा नंबर निम्न हैं:— हाल खसरा नंबर 5075 साबिक खसरा नंबर 3969 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, हाल खसरा नंबर 5076 साबिक खसरा नंबर 3970 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, हाल खसरा नंबर 5077 साबिक खसरा नंबर 3971 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा हाल 2.15 है० । उपरोक्त आराजियात से रेस्पोंडेंट का कोई संबंध नहीं है व महादेव की लाओलाद मृत्यु हो चुकी है

व महादेव के कोई जायंदा संतान नहीं है । उपरोक्त आराजियात पर कदीमी समय से अपीलांटस का कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं आज दिनांक को भी अपीलांटस का ही कब्जा काश्त है । उक्त आराजियात पर अपीलांटस संख्या 1 से 3 के दादा व 4 से 5 के पिता बोदू खां का कब्जा काश्त आजीवन रहा है । पूर्व में बोदू खां स्वयं उपरोक्त आराजियात पर काश्त करते रहे व उसके बाद अपीलांटस काश्त करते चले आ रहे हैं । संवत् 2011 में पर्चे जारी हुए, 4 वर्ष के कॉलम संख्या 5 में अन्य खसरा नंबरों के साथ बोदू खां के नाम काश्त दर्ज है व गिरदावरी संवत् 2015 से 2.18 के कॉलम नंबर 6 में बोदू स्वयं के नाम दर्ज रिकार्ड है व कॉलम नंबर 16 में बहैसियत काश्तकार उस्मान दर्ज है व खसरा गिरदावरी संवत् 2019 लगायत 2022 में पीरू पुत्र बोदू खां के नाम कॉलम नंबर 6 में इंद्राज दर्ज है । इस प्रकार जयपुर जिले में जमाबंदी नहीं बनती थी व गिरदावरी को ही राईट ऑफ रिकार्ड का दर्जा प्राप्त था । इस प्रकार [प्रार्थीगण/अपीलांटस](#) उपरोक्त आराजियात क खातेदार थे परन्तु भू-प्रबंध विभाग ने गलत तौर पर उपरोक्त आराजियात को महादेव के नाम दर्ज कर दिया जो फौत है । प्रार्थना पत्र के अंत में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी रेस्पों को पाबंद किया जावे कि वे अपीलांटस के कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं करे एवं मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे । उपरोक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांटस के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया व विपक्षी को नाटिस जारी करने के आदेश प्रदान किये जिस पर विपक्षी को नोटिस तामील होने के पश्चात् रेस्पों ने जवाब पेश किया । इसके अधीन्याया ने उभयपक्ष की बहस सुनकर बिना किसी आधार के अपीलांटस का कब्जा नहीं मानते हुए निर्णय दिनांक 23.8.2016 द्वारा [प्रार्थीगण/अपीलांटस](#) का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अधीन्याया के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों को तलब किया गया । रेस्पों के उपस्थित होने तथा अधीन्याया का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधीन्याया का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीन्याया ने धारा 212 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सभी राजस्व रिकार्ड को अनदेखा कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अधीन्याया ने इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांटस विवादित आराजियात पर वर्षों से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं व बंदोबस्त गिरदावरी में खुदकाश्त दर्ज रहे हैं जो अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत बंदोबस्त गिरदावरी संवत् 2008 से 2010 से पूर्णतया स्पष्ट है । इसी प्रकार खसरा गिरदावरी संवत् 2019 से 2022 में कब्जा काश्त है । इसके बावजूद अधीन्याया ने प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि जयपुर जिले में पूर्व में जमाबंदी नहीं बनती थी व खसरा गिरदावरी को ही राईट ऑफ रिकार्ड का दर्जा प्राप्त था । ऐसी स्थिति में अपीलांटस आराजी मुतनाजा के खातेदार काश्तकार थे परन्तु उपरोक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर अधीन्याया ने प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अधीन्याया ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू पर ध्यान नहीं दिया कि मान० राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत आर०आर०टी० 2006 पार्ट-प्रथम पेज 534 के विरुद्ध मान० राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मान० राजस्व मण्डल द्वारा दी गई ओनीनियन को स्टे किया हुआ है । ऐसी स्थिति में मान० राजस्व मण्डल द्वारा पारित

आदेश को आधार बनाकर निर्णय पारित नहीं किया जा सकता । इसके बावजूद भी अधी०न्याया० ने मान० राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्टे की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । अपीलांटस का वाद अधी०न्याया० के समक्ष विचाराधीन है जिसमें अपीलांटस के हक व अधिकारों का विनिश्चयन होना शेष है । ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट मेटर में निहित भूमि को सुरक्षित रखने के लिए यथास्थिति रखा जाना अनिवार्य है जिससे और अधिक वाद बाहुल्यता नहीं बढ़े । अधी०न्याया० ने प्रार्थना पत्र खारिज कर रेस्पों को एक प्रकार से खुली छुट प्रदान कर दी है । अपीलांटस ने अधी०न्याया० के समक्ष कब्जे काश्त के संबंध में पड़ोसी खातेदारों के शपथ पत्र पेश किये थे जिसके काउन्टर में रेस्पों द्वारा कोई काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया इसके बावजूद अधी०न्याया० ने रेस्पों का कब्जा काश्त मानते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि रेस्पों को खातेदारी तहसीलदार द्वारा धारा 19 के तहत दी गई है जो कि नियमों के विपरीत जाकर दी गई है । धारा 19 राज०काश्त०अधी० के तहत सिफ ए०सी०एम० कोर्ट ही न्यायालय खातेदारी देने में सक्षम है । प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्ण्य क्षति के बिन्दु अपीलांटस के पक्ष में निहित होने के बावजूद अधी०न्याया० ने [प्रार्थीगण/अपीलांटस](#) का प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी०न्याया० का आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पों संख्या 1 को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर०बी०जे० 1994 (1) पेज 24, ए०आइ०आर 2015 पेज 261 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पों संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि विद्वान अधी०न्याया० का आदेश विधिसम्मत है । विवादित आराजियात पर रेस्पों संख्या 1 के पिता महादेव का पर्चा सेटलमेंट के पूर्व से कब्जा था एवं महादेव के नाम आराजियात राजस्व रिकार्ड में जरिये नामांतरण संख्या 199 दिनांक 2.5.1960 को दर्ज हुई थी । उक्त इंद्राज वर्तमान में भी यथावत् है । विवादित आराजियात से अपीलांटस का कोई संबंध व सरोकार नहीं है तथा न ही कब्जा काश्त है । विद्वान वकील रेस्पों संख्या 1 ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलांटस विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नहीं है तथा न ही कब्जा काश्त है जिससे प्रथमदृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटस के पक्ष में नहीं बनता है । इसके विपरीत रेस्पों संख्या 1 विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर काबिज काश्त है यदि काबिज खातेदार काश्तकार को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो अपूर्ण्य क्षति भी रेस्पों संख्या 1 को ही होती है । विद्वान अधी०न्याया० ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों एवं राजस्व रिकार्ड का भली-भांति अवलोकन कर अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांटस का प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अधी०न्याया० का आदेश विधिसम्मत है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।
6. हमने उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात खसरा नंबर 5075 रकबा 0.66 है०, खसरा नंबर 5076 रकबा 0.86 है० एवं खसरा नंबर 5077 रकबा 0.63 है० वाके ग्राम मौजमाबाद, तह० मौजमाबाद, जिला जयपुर राजस्व रिकार्ड में रेस्पों संख्या 1 के पिता महादेव पुत्र रूघा के नाम दर्ज है । अपीलांटस ने विवादित आराजियात पर पुराने समय से कब्जे काश्त होने का कथन

किया है किन्तु कब्जे काश्त के संबंध में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । अपीलान्टस ने कब्जे के आधार पर खातेदारी एवं बेदखल नहीं किये जाने का अनुतोष चाहा है जबकि वर्तमान में विवादित आराजियात रेस्पो० संख्या 1 के पिता महादेव के नाम दर्ज रिकार्ड है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वाद अधी०न्याया० के समक्ष विचाराधीन है । उक्त वाद में अपीलान्टस को क्या हक व अधिकार प्राप्त होते है यह तो मूल वाद में बाद साक्ष्य निर्णित किया जावेगा किन्तु वर्तमान में रेस्पो० संख्या 1 के पिता महोदेव पुत्र रूघा दर्ज रिकार्ड है, जिन्हें किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना विधिसम्मत नहीं माना जाता है । प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णाय क्षति के बिन्दु अपीलान्टस के पक्ष में नहीं पाये जाने से अधी०न्याया० ने अपीलान्टस का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज०काश्त०अधि० खारिज किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्टस खारिज योग्य तथा अधी०न्याया० द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य पाया जाता है । अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है ।

7. अतः अपीलान्ट खारिज की जाती है । विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के आदेश दिनांक 23.8.2016 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी०एल०मेहरड़ा)

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 30.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी०एल०मेहरड़ा)

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर